

न्यूज टुडे

विश्व बैंक ने 'एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बना (Becoming a High-Income Economy in a Generation)' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत को 2047 तक उच्च आय वाला देश (HIC) बनने के लिए अगले 22 वर्षों में औसतन 7.8% की दर से विकास करना होगा।

▶ भारत 2007-08 में निम्न-मध्यम आय वाला देश (LMIC) बन गया था। उल्लेखनीय है कि भारत वर्तमान में 2032 तक उच्च-मध्यम आय वाला देश (UMIC) बनने की राह पर है।

2047 तक उच्च आय वाले देशों (HIC) के समूह में शामिल होने की राह में मौजूद प्रमुख चुनौतियां

▶ मंद संरचनात्मक परिवर्तन: आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारत में कार्यबल का 45% हिस्सा कृषि क्षेत्र में नियोजित है। इसके अलावा, पारंपरिक बाजार आधारित सेवाएं और निर्माण कार्य (कम उत्पादकता) मिलकर लगभग 30% का योगदान देती हैं।

⊕ इसके विपरीत, कुल रोजगार में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 11% थी और आधुनिक बाजार सेवाओं की हिस्सेदारी केवल 7% थी।

▶ निजी निवेश में गिरावट: 1990 के दशक के सुधारों के बाद देश में निजी निवेश में वृद्धि हुई। लेकिन 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में इसमें गिरावट देखी गई।

▶ जनसांख्यिकीय लाभांश का कम उपयोग: वर्ष 2000-19 के दौरान, कार्यशील आयु वर्ग की आबादी में 37.4% की वृद्धि हुई थी, लेकिन रोजगार में केवल 15.7% की वृद्धि हुई थी।

⊕ इस अवधि के दौरान, श्रम बल भागीदारी दर 58% से घटकर 49% हो गई, जो कि मध्यम आय वाले देशों के मानकों से कम है।

संवर्द्ध को बढ़ावा देने हेतु अपनाई जाने वाली मुख्य रणनीतियां

▶ निवेश को बढ़ावा देना: बेहतर वित्तीय विनियमों द्वारा, MSME क्षेत्र को आसानी से ऋण उपलब्ध कराकर और सरलीकृत FDI नीतियों के माध्यम से 2035 तक निवेश को GDP के 33.5% से बढ़ाकर 40% करना।

▶ रोजगार उत्पन्न करना: एग्रो-प्रोसेसिंग, विनिर्माण, परिवहन और केयर इकॉनमी जैसे रोजगार-समृद्ध क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।

▶ संतुलित क्षेत्रीय विकास पर फोकस करना: कम विकसित राज्य मूलभूत आवश्यकताओं (स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अवसरचनाओं के विकास) पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि विकसित राज्य अगली पीढ़ी के सुधारों को आगे बढ़ाते हैं।

पिछले 2 दशकों में भारत की आर्थिक संवर्द्धि

अर्थव्यवस्था के आकार में 4 गुना वृद्धि	प्रति व्यक्ति GDP में 3 गुना वृद्धि	वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी में 2 गुना वृद्धि
विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था	चरम निर्धनता में उल्लेखनीय कमी और बेहतर अवसरचना	महामारी से पहले GDP की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.7% थी

वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी: 1.6% (2000) → 3.4% (2023)

2047 तक उच्च आय वाले देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) को वर्तमान स्तर से 8 गुना बढ़ाना होगा

सरकार की प्रमुख योजना के अंतर्गत 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन किया गया

इन FPOs का गठन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत किया गया है। इस योजना को 29 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का नाम है- 10,000 नए FPOs के गठन और संवर्धन की योजना। 10,000 नए FPOs के गठन और संवर्धन की योजना के बारे में

▶ मंत्रालय: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

▶ आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित करना: इन जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में एक जिला एक उत्पाद (ODOP) क्लस्टर मॉडल के साथ कम-से-कम एक FPO का गठन सुनिश्चित किया गया है।

▶ आरंभिक समर्थन प्रदान करना: प्रत्येक गठित नए FPOs को पांच वर्ष की अवधि के लिए सहायता प्रदान की जाती रहेगी। इसके अलावा, सरकार प्रत्येक नए गठित FPO को प्रबंधन लागत हेतु 3 वर्षों के लिए 18 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

▶ FPOs की संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करना: इसके लिए पाल ऋणदाता संस्थानों से प्रति FPO 2 करोड़ रुपये तक के परियोजना ऋण की गारंटी सुविधा प्रदान की जाती है।

योजना के लाभ

▶ बाजार संबंधी लाभ: संयुक्त भंडारण और मूल्य संवर्धन सुविधाओं के माध्यम से फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

▶ वित्तीय लाभ: बेहतर मूल्य प्राप्ति और आर्थिक दबाव में फसलों की बिक्री को कम करने में मदद मिलती है।

▶ तकनीक और ज्ञान तक पहुंच: आधुनिक तकनीक एवं विस्तार सेवाओं आदि तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित होगी।

▶ संचार में आसानी: मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव की सूचना, बाजार के रुझान और सलाहकारी सेवाओं में मदद करती है।

योजना के तहत शुरू की गई पहलें

▶ FPOs के लिए ऋण गारंटी निधि: इसके तहत FPOs को ऋण प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों को ऋण गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।

▶ ONDC प्लेटफॉर्म: 5,000 FPOs अब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) में शामिल हो चुके हैं।

▶ 10,000 FPOs को कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) में परिवर्तित करना: डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करना।

FPOs के बारे में

▶ FPOs एक प्रकार का उत्पादक संगठन (PO) है, जिसके सदस्य आमतौर पर किसान होते हैं।

⊕ POs प्राथमिक उत्पादकों, जैसे- किसान, दूध उत्पादक, कारीगर आदि द्वारा गठित एक कानूनी इकाई हैं।

▶ उद्देश्य: कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन और विपणन में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से सामूहिक लाभ उठाना।

▶ पंजीकरण: FPO, किसानों और उत्पादकों का समूह होते हैं जो कंपनी अधिनियम के भाग IXA या संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं।

भारत-EU व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) की दूसरी बैठक भारत में संपन्न हुई

भारत-EU TTC की स्थापना 2022 में हुई थी। यह भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मंच है। इसका उद्देश्य व्यापार, विश्वसनीय तकनीक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान करना है।

इस परिषद के तहत तीन कार्य समूह बनाए गए हैं:

- रणनीतिक प्रौद्योगिकियां, डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल कनेक्टिविटी;
- स्वच्छ एवं हरित प्रौद्योगिकियां; तथा
- व्यापार, निवेश और लचीली मूल्य श्रृंखलाएं।

इस बैठक के मुख्य निष्कर्षों पर एक नजर

रणनीतिक प्रौद्योगिकियां, डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल कनेक्टिविटी:

- AI, सेमीकंडक्टर, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और 6G को मानव-केंद्रित तरीके से विकसित करने पर सहमति बनी।
- डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को इंटर-ऑपरेबल बनाने और यूरोपीय AI कार्यालय व भारत AI मिशन के बीच सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी।

हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियां:

- होराइजन यूरोप प्रोग्राम के तहत 60 मिलियन यूरो के संयुक्त निवेश के साथ समन्वित अनुसंधान शुरू करने की घोषणा की गई है।
 - होराइजन यूरोप यूरोपीय संघ (EU) का प्रमुख अनुसंधान और नवाचार वित्त-पोषण प्रोग्राम है।

व्यापार, निवेश और लचीली मूल्य श्रृंखलाएं:

- 2025 तक भारत-EU मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पूरा करने पर सहमति बनी।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की जांच करने के मामले में सर्वोत्तम प्रवृत्तियों का आदान-प्रदान किया जाएगा।
- यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकेनिज्म (CBAM) सहित व्यापार और डीकार्बोनाइजेशन पर चर्चा की गई।
- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC) के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई।

भारत और EU, दोनों बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं हैं तथा खुले बाजार, सुरक्षा, समृद्धि और संधारणीय विकास जैसे साझा मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए, बहु-ध्रुवीय विश्व में यह साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत-EU के बढ़ते व्यापारिक संबंध

EU भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि इस संबंध में भारत EU के लिए 9वें स्थान पर है।

2023 में द्विपक्षीय व्यापार 113.3 बिलियन यूरो तक पहुंच गया था।

भारत को 16.5 बिलियन यूरो का व्यापार अधिशेष हुआ था।

भारत से EU को निर्यात

M



मशीनरी

T



परिवहन

C



रसायन

EU से भारत को निर्यात

M



मशीनरी

A



विमान

E



विद्युत उपकरण

आदित्य-L1 के पेलोड ने सोलर फ्लेयर 'कर्नेल' की पहली तस्वीर ली

आदित्य-L1 के 'सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (SUIT)' पेलोड ने X6.3 श्रेणी की सोलर फ्लेयर का अवलोकन किया है। X6.3, सौर विस्फोटों की सबसे प्रबल श्रेणियों में से एक है।

आदित्य-L1 सोलर फ्लेयर का अध्ययन कैसे करता है?

सौर फ्लेयर के दौरान, सूर्य का वह विशेष क्षेत्र, जहां फ्लेयर उत्पन्न होती है, अल्ट्रावायलेट (UV) और एक्सरे में अधिक प्रज्वलित हो जाता है। आदित्य-L1 में लगे SUIT, SoLEXS और HEL1OS जैसे उपकरण प्रज्वलन वाले इन क्षेत्रों का अध्ययन कर सकते हैं।

SUIT: इसके निम्नलिखित दो कार्य हैं-

- सौर प्रकाश-मंडल (Solar Photosphere) और क्रोमोस्फीयर की नियर-अल्ट्रावायलेट (UV) तरंगदैर्घ्य में तस्वीरें लेना, तथा
- UV विकिरण में बदलाव को मापना।

SoLEXS और HEL1OS उपकरण: सूर्य से एक्सरे के उत्सर्जन का अध्ययन करना।

आदित्य-L1 मिशन के बारे में

मिशन लॉन्च: इसे सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है।

अंतरिक्षयान की अवस्थिति: इसे सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के लैंग्रेंज पॉइंट-1 (L1) के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा (Halo orbit) में स्थापित किया गया है

लैंग्रेंज पॉइंट्स पर दो विशाल द्रव्यमान वाले पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और किसी छोटे पिंड को उनके साथ-साथ घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल (centripetal force), दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार यहां पर स्थापित अंतरिक्षयान अपने नियत बिंदु पर बने रहते हैं।

उद्देश्य: इस मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- सूर्य के ऊपरी वायुमंडल (क्रोमोस्फीयर और कोरोना) की गतिशीलता का अध्ययन करना,
- क्रोमोस्फीयर और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन करना,
- कोरोनल मास इजेक्शन (CME) का विश्लेषण करना आदि।

आदित्य-L1 के पेलोड्स: इस मिशन के कुल सात पेलोड्स हैं, जो निम्नलिखित हैं-

- रिमोट सेंसिंग पेलोड्स: विज़िबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ (VELC), सोलर अल्ट्रा-वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (SUIT), सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (SoLEXS) तथा हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (HEL1OS);
- इन-सिटू पर्यवेक्षण पेलोड्स: आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट (ASPEX), प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य (PAPA), एडवांस्ड ट्राई-एक्सिसल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर आदि।

सोलर फ्लेयर क्या होते हैं?

ये सूर्य के वायुमंडल से प्रकाश/ विकिरण और उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों के रूप में सौर ऊर्जा का अचानक एवं प्रबल विस्फोट होते हैं।

प्रकार: सोलर फ्लेयर को उनकी प्रबलता के आधार पर पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ये श्रेणियां A, B, C, M, और X हैं। इनमें से प्रत्येक श्रेणी ऊर्जा उत्पादन में अपने पहले की श्रेणी से दस गुना वृद्धि दर्शाती है।

पृथ्वी पर प्रभाव:

- ये रेडियो ब्लैकआउट का कारण बन सकते हैं;
- सैटेलाइट्स, संचार प्रणालियों, पृथ्वी पर स्थित प्रौद्योगिकियों और विद्युत ग्रिड को नुकसान पहुंचा सकते हैं;
- अंतरिक्ष यात्रियों के समक्ष भी खतरा पैदा कर सकते हैं।

राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटीज/ टर्मिनल्स का निर्माण) विनियम, 2025 प्रस्तुत किए गए

ये विनियम भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने तैयार किए हैं। इनका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना है।

➤ भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जलमार्गों के विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है। यह एजेंसी पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।

मुख्य विनियमों पर एक नजर:

- कार्यक्षेत्र: विनियमों में मौजूदा और नए दोनों तरह के टर्मिनल्स को कवर किया गया है, चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी। अस्थायी टर्मिनल्स की अवधि 5 साल होगी, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है।
- अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NoC): कोई भी कंपनी या संस्था (सरकारी या निजी) जो राष्ट्रीय जलमार्ग पर टर्मिनल बनाना या संचालित करना चाहती है, उसे प्राधिकरण (IWAI) से NoC लेनी होगी।
- टर्मिनल डेवलपर और ऑपरेटर की जिम्मेदारियां: जो भी कंपनी टर्मिनल बनाएगी या संचालित करेगी, उसे तकनीकी डिजाइन और निर्माण का ध्यान रखना होगा। यह उसके बिजनेस प्लान के अनुसार होना चाहिए तथा वहां लोगों को पर्याप्त पहुंच भी मिलनी चाहिए।
- टर्मिनल के उपयोग के लिए डिजिटल पोर्टल: ईज ऑफ़ इडिंग बिजनेस के लिए दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने हेतु प्राधिकरण द्वारा एक पोर्टल विकसित किया जाएगा।

अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्रमुख पहलें

- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016: इस कानून के तहत अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
- 'जलवाहक' योजना: इस योजना के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा), राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र) और राष्ट्रीय जलमार्ग-16 (बराक) के जरिए कार्गो परिवहन करने पर 35% तक खर्च की प्रतिपूर्ति मिलती है। ये भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के अंतर्गत आते हैं।
- अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद् (IWDC): यह IWAI द्वारा संचालित एक उच्चस्तरीय नीतिगत मंच है। इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित करना और बढ़ावा देना है।

अंतर्देशीय जलमार्गों का महत्व

तीव्र और बिना रुकावट के विकास

जलमार्ग और टेलवे के विपरीत, जलमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे देरी और लागत में वृद्धि से बचा जा सकता है।

लागत प्रभावी परिवहन

जलमार्ग अन्य परिवहन साधनों की तुलना में सस्ता होता है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होती है।

RITES के अध्ययन के अनुसार, 1 लीटर ईंधन द्वारा कार्गो परिवहन क्षमता:

	24 टन/ किमी सड़क मार्ग से		95 टन/ किमी रेल मार्ग से		215 टन/ किमी अंतर्देशीय जलमार्ग से
--	------------------------------	---	-----------------------------	---	--

कार्गो यातायात में हुई तीव्र वृद्धि पर एक नजर

- पिछले एक दशक में कार्गो यातायात 22.1% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा है।
- कार्गो परिवहन 2013-14 में 18.07 MMT से बढ़कर 2023-24 में 133 MMT तक पहुंच गया।
- माल ढुलाई की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 5% करने का लक्ष्य, जिसके तहत:
 - 2030 तक 200+ MMT (समुद्री भारत विज़न); तथा
 - 2047 तक 500+ MMT (समुद्री अमृत काल विज़न) का लक्ष्य रखा गया है।

इंडिया फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट 2025 में भारत के सामाजिक क्षेत्रक संबंधी वित्त-पोषण के रुझान को उजागर किया गया

इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सामाजिक क्षेत्रक पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक दोनों के योगदान को मिलाकर वार्षिक रूप से GDP का 6-7% खर्च किया जाता है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- भारत के सामाजिक क्षेत्रक का वित्त-पोषण: यह पिछले पांच वर्षों में 13% CAGR के साथ वित्त-वर्ष 2024 में लगभग 25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। साथ ही, वित्त वर्ष 2029 तक इसके 45 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
 - इस वृद्धि के पीछे उभरती अर्थव्यवस्था, प्रवासी भारतीय और संरचनात्मक सुधारों का योगदान है।
- मुख्य चिंताएं:
 - निजी क्षेत्रक का कम योगदान: कुल व्यय का केवल 5% तक।
 - ♦ निजी क्षेत्रक का योगदान मुख्य रूप से हाई-नेट-वर्थ वाले व्यक्तियों (HNIs) के पारिवारिक दान और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड से आता है। उदाहरण के लिए राधा गोयनका द्वारा हेरिटेज प्रोजेक्ट (2018), गोदरेज इंडस्ट्रीज द्वारा प्राइड फंड (2025)।
 - वित्त-पोषण में कमी: भारत के सामाजिक क्षेत्रक में वित्त-पोषण प्रवाह 2023-24 के लिए नीति आयोग की सिफारिश से लगभग 14 लाख करोड़ रुपये कम रहा है।
 - ♦ नीति आयोग ने सामाजिक क्षेत्रक के वित्त-पोषण को GDP का 13% करने की सिफारिश की है।

भारत में विकास के साधन के रूप में लोकोपकार (फिलैंथ्रोपी) का महत्व

- वित्त-पोषण में कमी को पूरा करना: यह सरकारों द्वारा दी जाने वाली महत्वपूर्ण बजटीय सहायता को अतिरिक्त समर्थन प्रदान करता है।
- विकास संबंधी समस्याओं को हल करना: इससे गरीबी उन्मूलन और शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकता है।
 - उदाहरण के लिए- अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन ग्रामीण सार्वजनिक शिक्षा में सुधार हेतु काम करता है।
- नवाचार को बढ़ावा देना: इससे डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम/ स्वास्थ्य देखभाल सेवा स्टार्ट-अप जैसी तकनीक-संचालित पहलों को समर्थन प्रदान किया जा सकता है।
 - उदाहरण के लिए- बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन स्वच्छ भारत मिशन के साथ स्वच्छता संबंधी नवाचारों को समर्थन प्रदान करता है।

निजी क्षेत्रक द्वारा सामाजिक क्षेत्रक हेतु वित्त-पोषण को बढ़ावा देने वाली प्रमुख पहलें

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR): कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों को अपने औसत निवल लाभ का 2% CSR गतिविधियों के लिए आवंटित करना अनिवार्य है।
- इंडिया फिलैंथ्रोपी अलायंस (IPA): यह भारत के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अग्रणी गैर-लाभकारी संगठनों का एक नेटवर्क है।
- भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE): यह एक विशेष प्लेटफॉर्म है, जहां सामाजिक उद्यम शेयर बाजार से पूंजी जुटा सकते हैं।

अन्य सुर्खियां



विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion)

कथित रूप से "भ्रामक और अपूर्ण" जानकारी देने के आधार पर विदेश मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया गया।

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में

- यह प्रस्ताव तब प्रस्तुत किया जाता है, जब किसी सदस्य को लगता है कि संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया गया है।
 - संसदीय विशेषाधिकार सांसदों को प्राप्त कुछ विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां हैं, ताकि वे अपने कर्तव्यों को प्रभावी रूप से निभा सकें। ये विशेषाधिकार व्यक्तिगत रूप से सांसदों और सामूहिक रूप से संसद को प्राप्त होते हैं।
- शर्तें: प्रस्ताव निम्नलिखित दो शर्तों पर प्रस्तुत करना होता है-
 - यह किसी विशिष्ट व हाल की घटना से संबंधित होना चाहिए; तथा
 - यह ऐसा मामला होना चाहिए, जिसमें सदन के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।
- अध्यक्ष/ सभापति स्वयं इस पर निर्णय ले सकता है या इसे संसद की विशेषाधिकार समिति को भेज सकता है।



बंजारा समुदाय

हाल ही में, लोक सभा अध्यक्ष ने देश की प्रकृति और परंपरा की रक्षा में बंजारा समुदाय की भूमिका की प्रशंसा की।

बंजारा (बेपारी, मुकेई, लाबान आदि) समुदाय के बारे में

- उत्पत्ति: बंजारा ऐतिहासिक रूप से बहुधार्मिक व बहुभाषी घुमंतू व्यापारिक जाति है। इनकी उत्पत्ति मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) से मानी जाती है।
- व्यापारी घुमंतू के रूप में भूमिका:
 - वे गांवों, कस्बों और यहां तक कि देश के अलग-अलग भागों में व्यापार करते हैं।
 - वे मुख्यतः अनाज, दालें, चीनी, नमक, लकड़ी और इमारती लकड़ी का व्यापार करते हैं।
 - बंजारे बड़े समूहों में यात्रा करते हैं जिन्हें टांडा कहा जाता है। प्रत्येक टांडे का नेतृत्व 'नायक' नामक एक सरदार करता है।
- ऐतिहासिक विवरण:
 - सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शहरों में अनाज पहुंचाने के लिए बंजारों की मदद ली थी।
 - सम्राट जहांगीर ने अपनी आत्मकथा 'तुजुक-ए-जहांगीरी' में उल्लेख किया था कि बंजारे बैलों पर गांवों से शहरों तक अनाज ले जाते थे।
 - उन्होंने सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेनाओं को खाद्यान्न की आपूर्ति की थी।



हिमस्खलन (Avalanche)

उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव के पास हिमस्खलन के बाद बर्फ के नीचे फंसे BRO श्रमिकों को सुरक्षित निकाला गया।

हिमस्खलन के बारे में

- परिभाषा: यह हिम/ बर्फ के एक बड़े पिंड का ढलान पर उच्च गति और व्यापक बल के साथ नीचे की ओर गति करने की परिघटना है। इससे इसके मार्ग में व्यापक विनाश होता है।
- हिमस्खलन के लिए उत्तरदायी कारक: बर्फ, जमीन की प्रकृति और मौसम संबंधी दशाएं।
- हिमस्खलन के प्रकार: हिमस्खलन के दो मुख्य प्रकार हैं-
 - असंगठित हिम का हिमस्खलन और बड़े खंड के रूप में हिमस्खलन। हिम की संरचना, संघटन आदि के आधार पर इन्हें आगे उप-विभाजित किया जाता है।
 - असंगठित हिम का हिमस्खलन: यह तब घटित होता है, जब बर्फ के क्रिस्टलों के बीच आंतरिक बंधन बहुत कम होता है। यह आमतौर पर खड़ी ढलान पर होता है, जहां बर्फ आसानी से खिसक जाती है।
 - बड़े खंड के रूप में हिमस्खलन: यह तब घटित होता है, जब बर्फ की परतें आपस में अच्छी तरह से जुड़ी होती हैं। इन परतों के मध्य बंधन इतना संगठित होता है कि वे एक संपूर्ण इकाई के रूप में ढलान से खिसक जाती हैं।



एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART)

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को HIV (मानव इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस) / एड्स/ AIDS (एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम) रोगियों के लिए ART दवाओं की निविदा और खरीद में पारदर्शिता के मुद्दों को हल करने का आदेश दिया।

एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) के बारे में

- ART दवाइयों का एक मिश्रण है, जो HIV को नियंत्रित करने में मदद करता है।
 - HIV एक वायरस है, जो CD4 कोशिकाओं (जिन्हें हेल्पर टी-कोशिकाएं भी कहते हैं) को नष्ट करता है। ये कोशिकाएं शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं।
- यह थेरेपी HIV का इलाज नहीं कर सकती है, हालांकि यह HIV के स्तर को कम जरूर कर सकती है।
 - वायरस के निम्न स्तर का अर्थ है कि CD4 कोशिकाओं का अधिक उत्पादन बढ़ सकता है। इससे प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट होने से बची रहती है।
- भारत ने HIV/ एड्स से निपटने के लिए 1992 में राष्ट्रीय एड्स एवं STD नियंत्रण प्रोग्राम (NCAP) शुरू किया था।

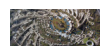


द्विपक्षीय स्वेप एग्रीमेंट (BSA)

भारत और जापान ने 75 अरब डॉलर के द्विपक्षीय करेंसी स्वेप समझौते को नवीनीकृत किया है।

द्विपक्षीय स्वेप एग्रीमेंट (BSA) के बारे में:

- यह दो केंद्रीय बैंकों के बीच एक समझौता है। इसके तहत वे एक मुद्रा के नकदी प्रवाह का दूसरी मुद्रा के नकदी प्रवाह से पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार विनिमय कर सकते हैं।
- भारत-जापान BSA का उद्देश्य: यह द्विपक्षीय करेंसी स्वेप व्यवस्था है, जिससे दोनों देश जरूरत पड़ने पर अपनी स्थानीय मुद्रा के बदले अमेरिकी डॉलर का विनिमय कर सकते हैं।
- महत्व: विनिमय दर की अस्थिरता को प्रबंधित करने और वित्तीय संकटों के दौरान तरलता प्रदान करने में सहायता करना।



ऑरोविले टाउनशिप

दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी उद्देश्यपूर्ण कम्युनिटी ऑरोविले ने हाल ही में अपनी 57वीं वर्षगांठ मनाई।

ऑरोविले टाउनशिप के बारे में

- परिचय: यह तमिलनाडु में पुडुचेरी के पास स्थित है। यहां 60 से अधिक देशों के लोग जीवन के शांतिपूर्ण वैकल्पिक तरीकों की खोज करते हैं।
- उत्पत्ति: 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। यह मीरा अल्फासा (मदर) के स्वप्न पर आधारित है, जो श्री अरविंदो के विचारों को व्यवहार में लाने पर केंद्रित है।
 - 1908 में श्री अरविंदो को अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इस अवधारणा में भारत को एक दिव्य शक्ति (मदर इंडिया) के रूप में दर्शाया गया था।
- मिशन: यह एक ऐसा केंद्र है, जहां भौतिक और आध्यात्मिक शोध किए जाते हैं, ताकि सच्ची मानव एकता प्राप्त की जा सके।
- मान्यता: 1966 में यूनेस्को ने इसे 'मानवता के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण परियोजना' के रूप में समर्थन दिया था।



भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)

देश के सबसे पुराने वैज्ञानिक संगठनों में से एक GSI का 175वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के बारे में

- उत्पत्ति: 1851 में सर थॉमस ओल्डम द्वारा स्थापित।
- नोडल मंत्रालय: खान मंत्रालय।
- मुख्यालय: कोलकाता।
- भूमिका: इसने भूवैज्ञानिक मानचित्रण, खनिज अन्वेषण, आपदा संबंधी अध्ययन और भूवैज्ञानिक अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभाई है। साथ ही, भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।



गिलोय (गुडूची)

पबमेड डेटा के अनुसार, पिछले एक दशक में गिलोय से जुड़े अनुसंधान में 376.5% की वृद्धि हुई है। यह तथ्य चिकित्सा में गिलोय के प्रति बढ़ती वैश्विक रुचि को दर्शाता है।

गिलोय के बारे में

- वानस्पतिक विशेषताएं: यह एक बेल वाली झाड़ी है, जो मेनिस्पर्मसी फैमिली से संबंधित है।
- कहां उगता है: यह भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थानिक पादप प्रजाति है। गिलोय 25-45°C तापमान तथा 500 मीटर तक की ऊंचाई वाले इलाकों में उग सकता है।
- मुख्य तत्व: इसमें टरपेनोइड्स, एल्कलॉइड्स, लिगनैन्स और स्टेरॉयड्स पाए जाते हैं।
- लाभ: इसमें रोगाणुरोधी, सूजन कम करने वाले, एंटीऑक्सीडेंट और मधुमेह नियंत्रण करने वाले गुण होते हैं।

सुर्खियों में रहे स्थल



चन्द्रशेखर वेंकट रमन (1888-1970)

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उनके द्वारा की गई 'रमन प्रभाव' की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

- रमन प्रभाव: जब प्रकाश किसी पदार्थ से टकराता है, तो वह उसके अणुओं के साथ संपर्क करके ऊर्जा का आदान-प्रदान करता है। इस प्रक्रिया के कारण कुछ बिखरा हुआ प्रकाश अपनी तरंगदैर्घ्य और रंग बदल लेता है।

- उदाहरण: समुद्र का नीला रंग इसलिए दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जल के कणों से टकराकर बिखर जाता है। आसमान का नीला रंग इसलिए दिखता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हवा के कणों से टकराकर बिखरता है।

सी.वी. रमन के बारे में

- जन्म: तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) में।
- स्थापना: इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज आदि।
- पुरस्कार:
 - 1929: नाइटहुड से सम्मानित।
 - 1930: भौतिकी में नोबेल पुरस्कार (रमन प्रभाव के लिए)।
 - 1954: भारत रत्न।
- मूल्य: वैज्ञानिक दृढ़ता, साहस, उत्कृष्टता, जिज्ञासा आदि।



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची